राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 177/2018

1. सज्जन @कल्ला पुत्र श्री वजीर सिंह, आयु- 25 वर्ष, जाति- जाट, निवासी- बालसमंद , पी. एस. सदर- हिसार (हरियाणा)

2. राकेश @कालिया पुत्र श्री सुरेश, उम्र- 23 साल, जाति- जाट, निवासी- खरमपुर, पी. एस.- आदमपुर, हिसार (हरियाणा) (वर्तमान में जिला जेल, हनुमानगढ़ में बंद)----अपीलकर्ता।

बनाम

लोक अभियोजक के माध्यम से राजस्थान राज्य----प्रतिवादी।

अपीलकर्ता(ओं) के लिए:- श्री जे.एस. चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री प्रदीप चौधरी एवं सुश्री सम्पति चौधरी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:-श्री बी.आर. बिश्नोई, पी.पी.।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र प्रकाश सोनी

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

09/01/2024

(माननीय श्री आर. पी. सोनी, जे. द्वारा):-

1. अपीलकर्ताओं ने 2015 के सत्र मामले संख्या 25 (सी. आई. एस. संख्या 25/2015) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भादरा, जिला हनुमानगढ़ की अदालत द्वारा दिए गए दिनांकित 08.08.2018 के निर्णय और आदेश जिसका शीर्षक "राजस्थान राज्य बनाम सज्जन

@कल्ला और अन्य" है, के विरूद्ध अपील की है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें निम्नानुसार सजा सुनाई गईः -

अपीलकर्ताः सज्जन @कल्ला:

धारा के तहत सजा	**सजा सुनाई गई**	**जुर्माना लगाया गया**	**जुर्माना डिफ़ॉल्ट सजा**
102-बी आईपीसी आई.पी.सी.	आजीवन कारावास	Rs.10,000/-	दो साल आर. आई.
302 आर/डब्ल्यू 109 आई.पी.सी.	आजीवन कारावास	Rs.10,000/-	दो साल आर. आई.
387 आर डब्ल्यू 109 आई.पी.सी.	सात साल की कैद	Rs.2,000/-	छह महीने आर. आई.

अपीलकर्ता: राकेश @ कालिया:

धारा के तहत सजा	**सजा सुनाई गई**	**जुर्माना लगाया गया**	**जुर्माना डिफ़ॉल्ट सजा**

102-बी आई.पी.सी.	आजीवन कारावास	Rs.10,000/-	दो साल आर. आई.
302 आर/ डब्ल्यू 109 आई.पी.सी.	आजीवन कारावास	Rs.10,000/-	दो साल आर. आई.
387 आर डब्ल्यू 109 आई.पी.सी.	सात साल की कैद	Rs.2,000/-	छह महीने आर. आई.
450 आई.पी.सी.	दस साल आर. आई.	Rs.3,000/-	एक वर्ष आर. आई.
3/25 शस्त्र अधिनियम	तीन साल आर. आई.	Rs.1,000/-	एक महीने आर. आई.
27 शस्त्र अधिनियम	तीन साल आर. आई.	Rs.1,000/-	एक महीने आर. आई.

सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।

2. आइए हम पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मामले का एक बहुत ही संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स दें।

3. यह कि दिनांक 23.02.2015 को शिकायतकर्ता के विरुद्ध, कुलदीप सिंह (पीडब्लू-2) ने एस. एच. ओ., थाना भादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ, उसके चचेरे भाई शिशराम @ शिशपाल@ पप्पु के पास एक मोटरसाइकिल कार्यशाला है जो भादरा शहर में बस स्टैंड के पास स्थित है। शिकायतकर्ता उस दिन 06:15 बजे तक शीशराम के साथ कार्यशाला में था। इसके बाद वे अपने गांव लौट आए। लगभग 1.00 बजे, मनोज सिंह (पीडब्लू-5) ने शिकायतकर्ता को फोन किया और उसे सूचित किया कि तीन अज्ञात बदमाश कार्यशाला में घुस गए थे, शीशराम पर गोली चला दी और घटनास्थल से भाग गए। शिशराम को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यह खबर सुनकर, कुलदीप सिंह और उनके भाई अशोक तुरंत अस्पताल पहुंचे। शीशराम के शरीर पर बंदूक की गोली से चोटें आई थीं और हमलावरों द्वारा किए गए हमले में उसने दम तोड़ दिया था।

4. उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जांच शुरू की गई और जांच पूरी होने के बाद, सह-आरोपी विरेंद्र उर्फ बिंद्रा उर्फ धनगर और साज्जिद खान के साथ अपीलार्थियों के खिलाफ चालान दायर किया गया।

5. मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के बाद, अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, विद्वान अदालत ने सह-आरोपी विरेंद्र उर्फ बिंद्रा उर्फ धनगर और साज्जिद खान को किशोर निर्धारित किया, इसलिए, उनका मामला आगे की सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड, हनुमानगढ़ को भेजा गया।

6. अपीलार्थी सज्जन उर्फ कल्ला पर भारतीय दंड संहिता की

धारा 120-बी, 109 के साथ पठनीय धारा 386 और 109 के साथ पठनीय धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया और अपीलार्थी राकेश उर्फ कालिया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 386,450,302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 27 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया। दोनों अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किये जाने की मांग की।

7. अपीलार्थियों के अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों से पूछताछ की और मुकदमे के दौरान विभिन्न दस्तावेजों और लेखों को भी प्रदर्शित किया।

8. दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में, दोनों अपीलार्थियों ने अभियोजन के साक्ष्य में अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अपने निर्दोष होने और झूठा फंसाने की दलील दी। अपने बचाव में किसी भी अपीलार्थी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, हालांकि कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे।

9. साक्ष्य के विश्लेषण पर, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 08.08.2018 के निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें सजा सुनाई।

10. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. एस. चौधरी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय कानून और तथ्यों के खिलाफ है जो कानून की नजर में बरकरार नहीं है और खारिज किए जाने के योग्य है क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने दोनों अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा देने में गलती की है। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विशुद्ध

रूप से उन अनुमानों और अटकलों पर आधारित है जो खामियों और विकृति से ग्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने सच्ची कहानी को दबा दिया है और केवल हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री को देखे बिना दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया है। जिस वास्तविक तरीके से यह घटना हुई, न तो गवाहों द्वारा बताया गया है और न ही जांच अधिकारी ने इसकी जांच की है। अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित फैसले को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जाना चाहिए। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः -

1. केहर सिंह और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1988 (एससी) 1883

2. बशीरा बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम 2020 आपराधिक कानून रिपोर्ट (एससी) 436

3. महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू गोपी नाथ 2000 आकाशवाणी (एससी) 1691

4. हंसराज बनाम राजस्थान राज्य 2014 (1) आपराधिक कानून रिपोर्ट(राज.) 1

5. मोहन सिंह परिहार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2013 ओ सुप्रीम (राज.) 1319

11. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक श्री बी. आर. बिश्नोई ने हमें पूरे साक्ष्य के माध्यम से

अवगत कराया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सभी साक्ष्य और लिंक उचित संदेह से परे साबित हुए हैं। अभियोजन पक्ष आपराधिक साजिश, उपशमन, उद्देश्य और बरामदगी के तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह केवल अपीलार्थी और उनके सह-अभियुक्त थे, जिन्होंने मृतक शीशराम की हत्या की थी। अपीलार्थियों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री और साक्ष्य की पहचान करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा देने में सही था। इसलिए, वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

12. हमने बार में पेश की गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया है और आक्षेपित फैसले का अध्ययन किया है। हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की भी पूरी तरह से विवेचना की है।

13. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जांच अधिकारी ने केवल एक सफल जांच सुनिश्चित करने के लिए एक कथित धमकी पत्र (ई. एक्स. पी.-109) को गलत तरीके से प्रत्यारोपित करके अपीलार्थी सज्जन @कल्ला को फंसाया है। धमकी पत्र (ई. एक्स. पी.-109) की खोज और बरामदगी के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय और दूषित है। मृतक को धमकी के उक्त पत्र के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हुआ है।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता सज्जन उर्फ कल्ला ने कभी भी धमकी भरा पत्र नहीं लिखा और ऐसा कोई पत्र मृतक शीशराम को नहीं भेजा गया या नहीं दिया गया। उन्होंने मृतक से धन की किसी भी अवैध मांग में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि धमकी पत्र पर अपीलकर्ता सज्जन @कल्ला की

लिखावट नहीं है।

15. उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि पुलिस अपराध स्थल को संरक्षित करने में विफल रही है। अपराध स्थल के संरक्षण की कमी मृतक की कार्यशाला से कथित धमकी - पत्र को बरामद करने की किसी भी संभावना को समाप्त कर देती है, इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि यह मनगढ़ंत और नकली बरामदगी है जो अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करती है।

16. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जाँच के दौरान अपराध स्थल का तत्काल निरीक्षण और जाँच अधिकारी द्वारा फर्द तैयार करने का पालन नहीं किया गया था। इससे जाँच की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठते हैं।

17. यह आगे तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी सज्जन @कल्ला का नमूना हस्त-लेखन कानून के अनुसार लिया गया था।

18. अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को अवैध रूप से दोषी ठहराया गया है।

19. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष का मामला गवाहों के बयानों से अच्छी तरह से पुष्ट है और पूरा साक्ष्य अपीलार्थियों के अपराध का समर्थन करता है। इसके संस्करण को बदनाम करने के लिए सबूत में कोई सामग्री, अनियमितता या कोई विसंगति नहीं है, इसलिए, विद्वत ट्रायल कोर्ट का निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

20. उपरोक्त तर्कों के आलोक में अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी सज्जन @कल्ला के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला साजिश और उपशमन के सिद्धांत पर आधारित था। आपराधिक साजिश का हिस्सा होने के अलावा अन्य अपीलार्थी राकेश

उर्फ कालिया के खिलाफ मृतक पर हमला करने में सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया गया था। तदनुसार यह है कि दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत भी आरोप तय किया गया था और अन्य आरोपों के अलावा अपीलार्थी सज्जन उर्फ कल्ला के खिलाफ प्रमुख अपराधों के साथ पठित धारा 109 का आरोप तय किया गया था।

21. अपराध का उद्देश्य Rs.50 लाख की अवैध मांग कहा जाता है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला, राकेश उर्फ कालिया, विरेंद्र उर्फ बिंद्रा उर्फ धनगर और सज्जिद खान कथित तौर पर सामूहिक रूप से शिशराम की हत्या करने की साजिश रचते हैं। अभियुक्त सज्जन @कल्ला, 50,00,000 रुपये की उगाही करना चाहता है। मृतक शीशराम ने अन्य तीन सह-अभियुक्तों को शीशराम को कथित धमकी पत्र (EXP-109) देने के लिए उकसाया। यह धमकी भरा संदेश मृतक शीशराम को सह-अभियुक्त द्वारा दिया गया था। रंगदारी की मांग को पूरा करने में शीशराम की विफलता पर, आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों को शीशराम को मारने के लिए उकसाया। नतीजतन, उसके तीनों सहयोगी राकेश उर्फ कालिया, विरेंद्र उर्फ बिंद्रा उर्फ धनगर और सज्जिद खान शीशराम की कार्यशाला में गए जहां वे शीशराम को गोली मारने के लिए आगे बढ़े और उसे मार डाला। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वास्तव में, चारों अभियुक्तों के दिमाग में साजिश रची गई थी। उन्होंने शीशराम को एक बड़ी राशि यानी Rs.50,00,000/- की रंगदारी की राशि देने के लिए मजबूर करने का विचार किया और यदि वह मना कर देता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अपीलार्थी सज्जन उर्फ कल्ला के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी इमारत कथित आपराधिक साजिश और उपशमन पर बनाई गई थी जिसमें सह-अपीलार्थी राकेश भी

शामिल था। जैसा कि पहले कहा गया है, सह-अपीलार्थी राकेश के खिलाफ भी सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया गया था। निस्सन्देह अपीलार्थी सज्जन उर्फ कल्ला को कथित अपराध की घटना के दिन हिसार जेल में रखा गया था।

22. प्रारंभ में, हम धमकी पत्र (ई. एक्स. पी.-109) की बरामदगी की परिस्थितियों को समझना चाहेंगे, जिसे कथित रूप से अपीलार्थी सज्जन @कल्ला द्वारा लिखा गया था और मृतक शीशराम को भेजा गया था। यह धमकी भरा पत्र सबूतों की श्रृंखला में मुख्य कड़ी है। अपीलार्थी सज्जन @कल्ला को कथित धमकी - पत्र के आधार पर फंसाया गया है, जिसके बारे में कहा गया था कि यह फर्द बरामदगी (ई. एक्स. पी.-6) के माध्यम से शीशराम की कार्यशाला से बरामद किया गया था।

23. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला ने मृतक शीशराम से 50,00,000 रुपये की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि इस मांग को पूरा न करने के कारण शीशराम की हत्या हुई। कहा जाता है कि आरोपी सज्जन @कल्ला द्वारा मृतक को भेजा गया धमकी पत्र सबूत का एक महत्वपूर्ण भाग है।

24. धमकी पत्र (ई. एक्स. पी.-109) की विषय वस्तु इस प्रकार हैः -

"मेरे आदमी को 50 लाख रू0 दे देना वरना अजांम बुरा होगा।

सज्जन / काला बालसमन्दिया।"

25. मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना 23.02.2015 को लगभग 07:15 बजे हुई थी, जबकि धमकी भरा पत्र 25.02.2015 को सुबह 09:15 पर घटना स्थल से बरामद किया गया था। घटना के

तीसरे दिन जो एक स्वीकृत तथ्य है।

26. अब, घटना स्थल से धमकी - पत्र की खोज और बरामदगी के संबंध में अभियोजन के दावे की विश्वसनीयता पर विचार किया जाता है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह (पीडब्लू-2) न केवल मृतक के परिवार का सदस्य है, बल्कि मृतक के साथ कंप्यूटर से संबंधित काम संभालने वाली उसकी कार्यशाला में भी काम करता था। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में कहाः-"मैं कार्यशाला में कंप्यूटर से संबंधित कार्य करता था। शीशराम मेरा चचेरा भाई है। कार्यशाला में मेरे कंप्यूटर के अलावा कोई अन्य कंप्यूटर नहीं थे। मैं कंप्यूटर काउंटर पर लेखांकन डायरी और कागजात रखता था। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कंप्यूटर काउंटर पर सभी लेखांकन डायरी और कागजात का ध्यान रखता था। मैंने कभी भी शीशराम को 50 लाख रुपये की मांग करने वाला धमकी - पत्र होने या मिलने के बारे में सूचित नहीं किया। मुझे कभी भी काउंटर पर रखे कागजातों के बीच Rs.50 लाख की मांग करने वाला कोई धमकी-पत्र नहीं मिला था। "

27. कुलदीप सिंह (पीडब्लू-2) के उपरोक्त बयान को ध्यान में रखते हुए, मृतक की कार्यशाला से धमकी - पत्र की खोज और बरामदगी की पूरी कहानी अत्यधिक संदिग्ध है और भरोसा किये जाने योग्य नहीं है। कथित धमकी पत्र से चुप रहने में मृतक का आचरण भी इस तरह के धमकी पत्र की बरामदगी को अत्यधिक असंभव बनाता है। कार्यशाला के कंप्यूटर संचालक, कुलदीप सिंह (पीडब्लू-2) के लिए यह बहुत ही असामान्य और संभावना नहीं है कि उन्हें अपने कंप्यूटर काउंटर में रखे गए इस तरह के धमकी - पत्र के बारे में कोई

जानकारी नहीं है, अगर यह वास्तव में मौजूद है। उम्मीद की जाती है कि कुलदीप सिंह को कंप्यूटर काउंटर के दराज में रखे गए सभी दस्तावेजों के बारे में पता होगा।

28. एक आम आदमी के लिए यह असंभव है कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद, वह इस पर चर्चा करने या अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगी, जो उसके परिवार के सदस्य भी थे, उन्हें इस बारे में बताने से बचे। इस तरह की धमकी के बाद भय की अनुपस्थिति या परिवार के सदस्यों को इस तरह के भय की अनुपस्थिति को संप्रेषित करने में विफलता समान रूप से असंभव है।

29. जाँच अधिकारी गोपाल सिंह ढाका (पीडब्लू-14) के बयान के साथ-साथ फर्द नक्शा मौका (ई. एक्स. पी.-7) के विश्लेषण से पता चलता है कि आई. ओ. ने घटना के तीसरे दिन अपराध स्थल का निरीक्षण किया और कथित रूप से धमकी भरा पत्र कार्यशाला में स्थित कंप्यूटर काउंटर के दराज से स्थल निरीक्षण के दौरान बरामद किया गया था। इस न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष अपराध स्थल के निरीक्षण में देरी को न्यायोचित और तर्कसंगत तरीके से साबित करने में सक्षम रहा है और यह भी तथ्य कि क्या कथित धमकी पत्र की बरामदगी उचित संदेह से परे स्थापित की गई है या नहीं। जाँच अधिकारी ने अपने बयान में अपराध स्थल का निरीक्षण करने में देरी का कोई कारण नहीं बताया है, भले ही उसके पास घटना की शाम को ही ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था। यदि कथित धमकी पत्र घटना के दिन ही बरामद हो जाता, तो उक्त धमकी पत्र के अस्तित्व और

इसकी बरामदगी की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होता।

30. विशेष रूप से हत्या जैसे मामलों में अपराध स्थल का तत्काल निरीक्षण जांच का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक मामले में सबूत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस की जाँच इस संबंध में अभियोजन पक्ष के पक्ष में पक्षपाती प्रतीत होती है। घटना के तुरंत बाद अपराध स्थल पर पहुंचने के बावजूद, जांच अधिकारी ने अपराध स्थल का तुरंत निरीक्षण और जांच नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने निरीक्षण को तीसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। यह देरी अभियोजन पक्ष को अपराध स्थल पर झूठे सबूत गढ़ने का अवसर प्रदान कर सकती थी। यह तथ्य अस्तित्व की विश्वसनीयता के साथ-साथ मृतक की कार्यशाला से धमकी पत्र की बरामदगी पर संदेह पैदा करता है।

31. अभियोजन पक्ष अपराध स्थल का फर्द तैयार करने में देरी की संतोषजनक व्याख्या करने के लिए बाध्य है जिसमें वह पूरी तरह से विफल रहा है जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्य और विश्वसनीयता को कम करता है जिसमें कथित धमकी पत्र के फर्द जब्ती के गवाहों का बयान और अपराध स्थल के फर्द निरीक्षण शामिल है। मृतक की कार्यशाला से धमकी - पत्र की बरामदगी की पूरी कहानी अत्यधिक संदिग्ध है और भरोसा किये जाने योग्य नहीं है।

32. यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या जांच अधिकारी ने अपराध स्थल को संरक्षित किया है। इस संदर्भ में, जाँच

अधिकारी ने कहाः-"मैं शाम को 07:10 पर अपराध स्थल पर पहुँचा। उस समय कार्यशाला खुली हुई थी। मैंने कार्यशाला को उसकी वर्तमान स्थिति में सुरक्षित किया और घटना स्थल की सुरक्षा के लिए वहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया। मुझे याद नहीं है कि किस पुलिस कर्मी को सुरक्षा ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था। इस तरह की तैनाती के संबंध में उस दिन की रोजनामचा डायरी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना स्थल का निरीक्षण करते समय पड़ोस से कोई भी मौजूद नहीं था। धमकी - पत्र में मृतक या उसके किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है।

33. जाँच अधिकारी के इन बयानों के आधार पर, यह उचित संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है कि जाँच अधिकारी द्वारा निरीक्षण से पहले घटना स्थल को संरक्षित किया गया था। जाँच अधिकारी द्वारा कोई फर्द तैयार नहीं किया गया था, जिसमें अपराध स्थल के संरक्षण के तथ्य का उल्लेख किया गया था और इस पहलू के बारे में रोज़नामचा में कोई प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी। घटना स्थल की सुरक्षा करने वाले कर्मियों को भी मुकदमे के दौरान गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है और रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज या फर्द उपलब्ध नहीं है जो मृतक की कार्यशाला की सीलिंग और अन-सीलिंग को साबित करता है।

34. ऐसी परिस्थितियों में, यह साबित होना नहीं माना जा सकता है कि घटना के तीसरे दिन जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने तक घटना स्थल बरकरार रहा और दो रातों तक संरक्षित रहा। चूंकि अपराध स्थल बरकरार और संरक्षित नहीं रहा, इसलिए जांच

अधिकारी द्वारा घटना के तीसरे दिन अपराध स्थल का निरीक्षण करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अभियोजन पक्ष के मामले पर इसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह एक महत्वपूर्ण और बड़ी चूक है। इस चूक ने सबूतों को समाप्त कर दिया है, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया है और कथित धमकी पत्र की बरामदगी के बारे में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। अपराध स्थल के उचित संरक्षण की उपेक्षा करने से गंभीर कानूनी परिणाम होते हैं जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम करते हैं। इसने अलंकरण, रंगीन संस्करण और मनगढ़ंत कहानी की शुरुआत भी की है।

35. पीडब्लू-23 जीतू सिंह हैं जो उस समय तहसीलदार के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे। इस गवाह की गवाही धमकी पत्र (ई. एक्स. पी.-109) की लिखावट स्थापित करने से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने इस कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला की नमूना लिखावट (ई. एक्स. पी.-89 से 103) प्राप्त की है। प्राप्त नमूना हस्ताक्षर को तुलना के लिए एफ. एस. एल. को भेजा गया था और एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार, धमकी पत्र की लिखावट का मिलान आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला के नमूना हस्तलेखन से किया गया था।

36. जीतू सिंह (पीडब्लू-23) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने से पहले, उन्होंने आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला की पहचान पुलिसकर्मियों या उसे पेश करने वाले जांच अधिकारी द्वारा नहीं कराई थी। उन्होंने नमूना हस्तलेखन के पत्रकों पर

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर लिये।

37. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उपरोक्त बयानों को देखते हुए, यह साबित नहीं होता है कि किस ने आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला को नमूना लिखावट लेने की कार्यवाही करने के लिए उसके सामने पेश किया था। यह भी साबित नहीं हुआ है कि किसने आरोपी सज्जन @कल्ला को पहचाना। यह भी साबित नहीं हुआ है कि जाँच अधिकारी ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी की पहचान की थी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा आरोपी को पेश करने के लिए नमूना हस्ताक्षर के विभिन्न पत्रों पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं मिले। अभियोजन पक्ष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए किसी भी अग्रेषण पत्र को साबित करने में भी विफल रहा है, जिसमें नमूना लिखावट लेते समय उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है। नमूना हस्तलेखन (ई. एक्स. पी.-89 से 103) में भी इस तथ्य का कोई संकेत नहीं है कि आरोपी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने किसने पेश किया।

38. ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि धमकी पत्र आरोपी सज्जन @कल्ला की लिखावट में था। इसलिए, हम मानते हैं कि अपीलार्थी सज्जन @कल्ला की नमूना लिखावट कथित रूप से जांच के दौरान प्राप्त की गई है, जिसे खारिज किया जा सकता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि धमकी पत्र आरोपी सज्जन @कल्ला के हाथ से लिखा गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और इसे दरकिनार किया

जा सकता है।

39. अपीलार्थी सज्जन @कल्ला के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया एक और संबद्ध साक्ष्य हिसार जेल में हिरासत में रहने के दौरान उससे कागज की एक पर्ची (ई. एक्स. पी.-111) की खोज और बरामदगी है। कागज की इस पर्ची में सह-अभियुक्त सहित विभिन्न टेलीफोन नंबरों की सूची है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला को हिसार जेल के जांच अधिकारी ने 08.05.2015 को फर्द गिरफ्तारी (EXP-17) के दौरान पकड़ा था, तो उसकी जेब से उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान कागज की एक पर्ची मिली और बरामद की गई। इस साक्ष्य का उद्देश्य अभियुक्तों के बीच पहले से मौजूद संबंध, सह-अभियुक्तों के बीच टेलीफोन संचार और बातचीत और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक साजिश का अस्तित्व स्थापित करना है।

40. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला के लिए जेल में रहते हुए इस तरह के कागज की पर्ची रखना असंभव था और आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे दंडात्मक उपायों के अधीन किया, जिससे उसे पुलिस स्टेशन में उपरोक्त पर्ची लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दोनों जांच अधिकारियों गोपाल सिंह (पीडब्लू-14) और महेश कुमार (पीडब्लू-20) के बयानों को देखने के बाद, यह साबित होता है कि हिसार के किसी भी जेल कर्मचारी ने आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला की गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान गवाह के रूप में गवाही नहीं दी। अभियुक्त सज्जन के लिए जेल में रहते हुए कोई भी दस्तावेज रखना

असंभव था क्योंकि इस तरह की वस्तुओं को आम तौर पर जेल अधिकारियों द्वारा प्रवेश करने पर जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष सबूत स्थापित करने में विफल रहा है जो दर्शाता है कि आरोपी सज्जन उर्फ कल्ला के पास जेल में प्रवेश करते समय कागज की ऐसी पर्ची थी।

41. यह भी पता चलता है कि विचाराधीन पर्ची एक ताजा और बिना सलवट वाले कागज की प्रतीत होती है, जिससे पता चलता है कि इसे लंबे समय तक जेब में नहीं रखा गया था। पर्ची में सूचीबद्ध टेलीफोन नंबरों के बारे में कोई जांच नहीं की गई है। न तो उन नंबरों का सिम विवरण प्राप्त किया गया है और न ही उनके सीडीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। इस परिदृश्य में, उक्त पर्ची की वसूली की विश्वसनीयता में पर्याप्त, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है। नतीजतन, टेलीफोन नंबरों की उक्त पर्ची के आधार पर अभियुक्तों के बीच साजिश का अनुमान लगाना निराधार हो जाता है।

42. अभियुक्त सज्जन @कल्ला को वर्तमान घटना से जोड़ने के लिए जिस अन्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह है ई. एक्स. पी.-54 जो हिसार जेल में उसके रहने का विवरण दर्ज करता है। यह दस्तावेज़ अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के प्रयास में प्रस्तुत किया गया है कि सभी आरोपी घटना से पहले और बाद में एक-दूसरे के संपर्क में थे। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इस दस्तावेज़ के विवरण को उनके बीच आपराधिक साजिश का सबूत माना जाना चाहिए। इस न्यायालय के दृष्टिकोण से, अभियोजन पक्ष के उक्त तर्क का कोई बल नहीं है। यद्यपि, यह दस्तावेज़ आरोपी सज्जन @कल्ला

और अन्य सभी सह-अभियुक्तों के बीच बैठकों की आवृत्ति का विवरण देता है, हालांकि, (EXP-54) कई कारणों से इस मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता करने में विफल रहता है। मुख्य रूप से, यह जेल का मूल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसका सारांश है। इसके अतिरिक्त, इस सारांश को तैयार करने के लिए जिम्मेदार जेल अधिकारी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया था, कानून के अनुसार अप्रमाणित प्रतिपादन (ई. एक्स. पी.-54)। नतीजतन, यह दस्तावेज़ भी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि नहीं करता है।

43. सह-अपीलार्थी राकेश उर्फ कालिया पर आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 386,450 और 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 1 और 27 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। अन्य आरोपों के अलावा, उन्हें आपराधिक साजिश का एक अभिन्न अंग भी माना जाता था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वह कथित घटना में प्रत्यक्ष संलिप्तता का भी आरोपी था। जैसा कि पहले देखा गया है, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान मामले में सामूहिक रूप से किसी आपराधिक साजिश में शामिल थे।

44. अब, जहाँ तक वर्तमान घटना में अपीलार्थी राकेश @कालिया की प्रत्यक्ष संलिप्तता का संबंध है, बनवारी लाल (पीडब्लू-6) ने उक्त अभियुक्त की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्तमान मामले की कोई घटना उनके सामने नहीं हुई थी। उन्होंने वर्तमान एफ. आई. आर. की घटना नहीं

देखी। उन्होंने महेंद्र (पीडब्लू-1) के साथ 23.02.2015 को तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शीशराम को गोली मारते हुए नहीं देखा।

45. बनवारी लाल की उपरोक्त गवाही मौके पर और साथ ही परीक्षण पहचान परेड के दौरान सह-अपीलकर्ता राकेश @कालिया की पहचान से संबंधित अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रही। बनवारी लाल (पीडब्लू-6) के बयानों से उठाए गए संदेहों को देखते हुए, अन्य कथित चश्मदीद गवाह महेंद्र (पीडब्लू-1) की विश्वसनीयता भी सवाल के घेरे में आती है, जिससे उनकी गवाही भी अविश्वसनीय हो जाती है। इसलिए, इस घटना में सह-अपीलकर्ता राकेश @कालिया की संलिप्तता अप्रमाणित रही।

46. इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित सभी सहायक साक्ष्य अविश्वसनीय पाए गए हैं। नतीजतन, सह-अपीलार्थी राकेश के खिलाफ भी अभियोजन के मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं माना जा सकता है।

47. परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि पुलिस का यह दावा कि शिशराम @शिशपाल @पप्पु की हत्या दोनों अपीलार्थियों द्वारा आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने और आरोपी की धन की मांग को पूरा करने में विफल रहने के कारण की गई थी, अत्यधिक संदिग्ध है। यह इसकी सत्यता पर गहरा संदेह पैदा करता है और विद्वान विचारण न्यायालय ने घटना स्थल से धमकी पत्र की बरामदगी और आरोपी सज्जन @कल्ला की लिखावट के नमूने के साथ धमकी पत्र की लिखावट के मिलान पर गलत तरीके से भरोसा किया है।

48. आपराधिक साजिश आमतौर पर गोपनीयता में रची जाती

है, जिसके कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए अपराध को या तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से साबित किया जा सकता है। हालाँकि, यदि लिंक साक्ष्य अधूरा या अस्पष्ट है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अदालत में ठोस सबूत पेश करके, गहरी सूझ-बूझ के संबंध में पर्याप्त सबूत प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, जो एक आपराधिक साजिश रचने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, साजिश के अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि इसमें शामिल व्यक्ति को कार्रवाई के सभी चरणों का ज्ञान हो। वास्तव में, साजिश के मुख्य उद्देश्य/ लक्ष्य का ज्ञान मात्र, उपयुक्त दंडात्मक प्रावधानों के आकर्षण की गारंटी देगा। इस प्रकार, दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता करना, या एक अवैध कार्य करना, दंडात्मक क़ानून के तहत साजिश के अपराध की मूल आवश्यकता है।

49. इस मामले में एक बार आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत साजिश से संबंधित अभियोजन मामला विफल हो जाने के बाद, आई. पी. सी. की धारा 109 पर भरोसा किया जाता है, जो एक साजिश पर विचार करता है और कुछ और है जिसे साबित नहीं किया जा सकता। साजिश पर आधारित किसी भी अवैध कार्य या चूक को छोड़ दें, कोई भी साजिश खुद साबित नहीं होती है। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 109 की कोई भूमिका नहीं है है।

50. निचली अदालत ने केवल अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य को स्वीकार किया। केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने से दोषसिद्धि नहीं होगी। इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण

है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की उचित रूप से विवेचना नहीं की है। दृढ़ संदेह के अस्तित्व से कभी भी दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। जैसा कि हम पाते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि यह अपीलार्थी थे जिन्होंने अपराध किया था, हम निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए प्रवृत्त हैं, विशेष रूप से जब हम आपराधिक साजिश और उपशमन के मामले से निपट रहे हैं।

51. तदनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भादरा, जिला हनुमानगढ़ की अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश दिनांक 08.08.2018 के अनुसार, 2015 के सत्र मामले No.25 (CIS No.25/2015) में "राजस्थान राज्य बनाम सज्जन @कल्ला और अन्य" शीर्षक से पारित दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और वर्तमान आपराधिक अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। दोनों अपीलार्थी हिरासत में हैं, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए।

52. आदेश की एक प्रति विद्वत विचारण न्यायालय और अनुपालन के लिए तुरंत संबंधित जेल को भेजी जाए।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे (अरुण भंसाली), जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।